अध्याय- II

सबनधित शोध का पुनरावलोकन :

2.0.0 परिचय :

यह अध्याय उन संबंधित साहित्य की समीक्षा से संबंधित है जो शोधकर्ता द्वारा प्रस्तावित अध्ययन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। शोध पत्रिकाओं, पुस्तकों, शोध प्रबंध थीसिस और अन्य की विस्तृत समीक्षा। जांच की जाने वाली समस्या पर किसी भी शोध की योजना बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि शोधकर्ता अध्ययन की योजना के लिए पूर्व अनुरोध के लिए दिशा-निर्देश पा सके। दोहराव से बचें, चर के बीच समस्या संबंधों के स्रोत ।

2.1.0 महत्व:

एक साहित्य समीक्षा एक शोध समस्या पर चयनित शोध का प्रलेखन है। एक समीक्षा एक अनुसंधान प्रक्रिया का गठन कर सकती है या अपने आप में एक शोध परियोजना का गठन कर सकती है । साहित्य की समीक्षा पिछले शोध का महत्वपूर्ण संश्लेषण है । यह प्रस्तावित अध्ययन के लिए एक पृष्ठभूमि प्रदान करता है । संबंधित साहित्य की समीक्षा निम्नलिखित तरीके से की मदद करती है :

- विषय से संबंधित महत्वपूर्ण चर को मजबूत करना। एक नया दृष्टिकोण हासिल करना।
- विचारों और व्यवहार के बीच संबंध की पहचान करना विषय या समस्या के संदर्भ स्थापित करना ।
- समस्या के महत्व को तर्कसंगत बनाना।
- संबंधित विचारों और आवेदन करने के लिए सिद्धांत ।

2.2.0 संबंधित साहित्य की समीक्षा :

सुदेशना (1998) "छात्रों की उपस्थिति के कारण दिन के भोजन पर प्रभाव" का अध्ययन किया गया । विशेषण छात्रों की उपस्थिति और उपस्थिति पर मध्याह्न भोजन योजना के प्रभाव का अध्ययन करना था। अध्ययन के बिंदु थे। - (1) छात्रों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित करने में मध्याह्न भोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। (2) जिन स्कूलों में मिड डे मील की योजना है, वहां छात्रों की उपस्थिति बहुत है ।

मल्होत्रा (1998) ने "उपस्थिति, उपस्थिति और बच्चों की नियमितता पर प्रोत्साहन योजना का प्रभाव" विषय पर अध्ययन किया। विशेषण को बच्चों की नियमित उपस्थिति पर प्रोत्साहन योजना के प्रभाव का अध्ययन करना था। अध्ययन की शर्तें थीं (1) उन स्कूलों में बच्चों की नियमित उपस्थिति अधिक थी, जहां उन स्कूलों की तुलना में प्रोत्साहन योजनाएं (भोजन और छात्रवृत्ति) लागू की गईं, जहां कोई प्रोत्साहन योजना नहीं दी गई थी। (2) बालक बालिकाओं की अपेक्षा बालकों की संख्या अधिक थी । (3) जाति के आधार पर बच्चे की उपस्थिति में कोई अंतर नहीं पाया गया। (4) उपस्थिति पिछड़ी जाति का प्रतिशत अन्य जातियों की तुलना में अधिक था ।

सचदेवानंद (1999) "VEC की भूमिका समुदाय अब" गरिया (1999) ने "अब तक की ग्राम शिक्षा समिति और समुदाय की भूमिका का अध्ययन" पर अध्ययन किया। अध्ययन का उद्देश्य समुदाय और ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका और महत्व का अध्ययन करना था। अध्ययन के निष्कर्ष थे - (1) ग्राम शिक्षा समुदाय की स्थापना से संतुष्ट सभी समुदाय के सदस्य। (2) VEC सदस्य समुदाय के सदस्यों की मदद करते हैं। (3) VEC बच्चों की नियमित उपस्थिति में मदद करता है। (4) 55% माता-पिता और VEC प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं। (5) VEC ने समुदाय को हैंडपंप, बाथरूम, बाउंड्रीज, प्ले ग्राउंड आदि की सुविधाओं के लिए प्रेरित किया ।

त्रिपाठी (2000) "निर्माण जू भवन की मरम्मत में समुदाय के सदस्यों की भागीदारी का अध्ययन" पर अध्ययन किया गया। निर्माण और 87 में एसएमसी सदस्यों की भागीदारी का आकलन करें विद्यालय भवन की मरम्मत। अनुसंधान के बाद यह पाया गया कि सामुदायिक भागीदारी के कारण विद्यालय भवन के निर्माण और मरम्मत में काम की गुणवत्ता में सुधार होता है ।

दिल्ली के मिड डे मील योजना से अधिक लाभ की ओर सोमसुंग और क्लैरी (2007) की ओर। "कॉर्ड- सहयोगी अनुसंधान और प्रसार।" विद्यालय सर्वेक्षण में सभी बच्चों को उत्साहपूर्वक कतारबद्ध और प्रदान किए गए भोजन खाने का पता चलता है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राधिकरण कुछ सही कर रहा है । ऐसा बच्चा मिलना मुश्किल था जो खा नहीं रहा था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मिड डे मील अपने आप में स्कूलों में शिक्षण के माहौल को बाधित नहीं कर रहा है। यह देखने के लिए निश्चित रूप से ध्यान रखा गया है कि शिक्षक भोजन प्रक्रियाओं से बोझिल न हों ।

सिंह और मिश्रा (2010) ने "मेघालय में एमडीएम कार्यक्रम पर मूल्यांकन अध्ययन और कार्यान्वयन" पर एक अध्ययन किया। अध्ययन के विशेषण थे (1) कार्यक्रम के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए । (२) कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं और कड़वाहट का पता लगाना। (3) प्रोग्राममे के कामकाज में सुधार के लिए नीतिगत उपाय सुझाना। विचार इस प्रकार थे सभी हितधारक अधिकारियों, प्रबंधन, समिति, छात्रों की राय और अवलोकन माता-पिता यह दर्शाते हैं कि एमडीएम योजना ने किसी तरह नामांकन और उपस्थिति को बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षित की स्थिति में सुधार किया है । मिड डे मील के कार्यान्वयन के बाद ध्यान की अवधि में वृद्धि के बारे में प्रतिक्रिया ।

मैगारे (2010) ने "आरटीई -2009 पर शिक्षकों की धारणा" पर शोध किया, जिसमें पाया गया कि शिक्षक बाल अधिकारों के संतोषजनक स्तर के बारे में जानते थे । पुरुष और महिला शिक्षकों के बाल अधिकार साक्षरता स्तर में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, 24 - 35, 35 45 वर्ष के बीच आयु वर्ग में कोई अंतर नहीं है । ओपन और आरक्षित श्रेणी के शिक्षक के साथ-साथ अनुभव और 10 वर्ष से ऊपर के शिक्षक के बाल अधिकार साक्षरता स्तर में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है ।

जसीना फातिमा (2011) ने "आरटीई - ए स्टडी ऑन अवेयरनेस ऑफ एमएड ट्रेनीज" पर अध्ययन किया । शोधकर्ता ने निष्कर्ष निकाला कि शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है । लेकिन इन अधिकारों का उल्लंघन हर कोने से किया जाता है । नोवा दिवस के शिक्षकों को राष्ट्रीय भवन इंजीनियर माना जाता है । उन्हें समाज के मानदंडों के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करना होगा । इसलिए, शिक्षक शिक्षकों को शिक्षा क्षेत्र में वर्तमान ज्ञान से लैस होना चाहिए। अध्ययन से पता चला कि पुरुष एमएड छात्रों के पास है आरटीई (2009) की काफी अधिक जागरूकता। एमएड कॉलेजों के प्रबंधन का आरटीई (2009) के बारे में जागरूकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

देसाई(2010) "बच्चों के अधिकार के लिए सातवीं कक्षा के छात्र के दृष्टिकोण" पर एक अध्ययन किया। नियंत्रण समूह के मामले में बच्चे के अधिकार के लिए अनुकूल रवैया जबकि परिदृश्य प्रायोगिक समूह के मामले में आरक्षित है जो छात्रों के दृष्टिकोण को आकार देने में बच्चों के अधिकार पर क्रमबद्ध लागू शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। प्रयोगात्मक समूहों के छात्रों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है । दिल्ली में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए। और उन्हें बंद करने के बजाय, सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए । इन क्षेत्रों में गैर-

मान्यता प्राप्त स्कूलों में सबसे बड़ा लाभ छात्र-शिक्षक अनुपात और इसलिए वे समाज के निचले तबके के उन बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है । सरकारी स्कूलों में भी सभ्य स्कूली शिक्षा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा नहीं है । शोधकर्ता बताते हैं कि 925 इमारतों में 625 सरकारी विद्यालय कार्यरत हैं ।

व्यास (2011) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच जागरूकता पर **"द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पल्सरी एजुकेशन एक्ट, - 2009 (RTE)"** पर अध्ययन किया, इस प्रकार निष्कर्ष निकाला है: (1) कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है । पुरुष और महिला शिक्षक के बीच ग्रामीण शिक्षकों और शहरी शिक्षकों के बीच जागरूकता में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। (2) सरकारी शिक्षक और गैर-सरकारी शिक्षकों की जागरूकता की डिग्री के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है ।

अराक (2011) ने **"शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में शिक्षक की जागरूकता और राय"** पर अपना शोध किया। निष्कर्ष निम्नानुसार थे: (1) पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षक अपने शिक्षा के अधिकार अधिनियम -2009 (2) एस सी, एसटी शिक्षकों और अन्य श्रेणी के शिक्षकों के बारे में जागरूकता स्तर में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं हैं। (RTE 2009) आरटीई के संबंध में शिक्षकों की जागरूकता ।

दयानंद बीक (2011) ने "द राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री पेन कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट, 2009: टीचर परसेप्शन पर अध्ययन किया। अध्ययन के विचार थे ।

(1) अधिकांश शिक्षक आरटीई के बारे में जानते थे । (2) केवल 50% शिक्षक ही जानते थे । उस आयु समूह के बारे में जिस पर आरटीई प्रभावी है । (3) 40% से अधिक शिक्षकों का विचार था कि किस प्रकार के विद्यालय आरटीई लागू किए जाएंगे । (4) केवल 38% शिक्षकों ने ही समाचार पत्र खोलने के प्रावधानों और शर्तों को जाना था । (5) 25-35% शिक्षकों को कक्षा 6 और छठी-आठवीं में शिक्षकों और छात्रों के अनुपात के बारे में ज्ञान था। (6) केवल 18-20% शिक्षक प्रति सप्ताह काम करने के घंटे और शैक्षणिक दिनों में काम करने के बारे में जानते थे। सत्र। (7) 60% शिक्षक अधिनियम में कक्षा पदोन्नति के प्रावधान के बारे में जानते थे । (8) केवल 18-20% शिक्षकों को अधिनियम में पाठ्यक्रम के निर्माण के बारे में विचार था। (9) 30% शिक्षकों के बारे में विचार था । अधिनियम सहित वित्तीय बंटवारे। (10 में से अधिकांश शिक्षक व्यवस्था और उत्तीर्ण करने के पक्ष में नहीं थे।) (11) प्रवेश परीक्षा की जांच युवा और वरिष्ठ शिक्षकों की जागरूकता और राय की तुलना की गई है ।

अधिकांश मामलों में यह देखा गया कि वरिष्ठ शिक्षक आरटीई (2009) के बारे में कम जानते थे ।

प्रेम लक्ष्मी (2011) ने **आरटीई और कॉमन विद्यालय सिस्टम पर शोध किया। शिक्षकों के बीच धारणा।** अध्ययन के नतीजे थे- (1) कॉमन विद्यालय सिस्टम के प्रति पुरुष और महिला शिक्षकों के बीच धारणा में महत्वपूर्ण अंतर है । (2) कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है । सीएसएस के लिए शहरी और ग्रामीण शिक्षकों के बीच धारणा में । (3) सामान्य तौर पर, मैट्रिकुलेशन और सरकारी विद्यालय के शिक्षकों की राय सीएसएस के बीच अलग-अलग होती है । शर्मा और कुमार (2011) ने "आरटीई (2009) के प्रति अभिभावकों और शिक्षकों के बारे में जागरूकता" पर काम किया । निष्कर्ष थे - (1) शिक्षा के अधिकार अधिनियम (2009) के जागरूकता स्तर और शिक्षकों के अभिभावकों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है । माता-पिता की तुलना में शिक्षक काफी अधिक जागरूक हैं । (2) अधिकांश शिक्षकों का गठन आरटीई (73.12%) में हुआ था । उच्च और निम्न समूह क्रमशः 11% और 13% का प्रतिनिधित्व करता है। (3) अधिकांश माता-पिता मामूली रूप से पाए गए । शिक्षा का अधिकार अधिनियम (70%) के बारे में पता है । उच्च और निम्न समूह क्रमशः 41% और 16% का प्रतिनिधित्व करता है ।

पांडा और मोंडल (2012) ने **"छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर मिड-मील भोजन कार्यक्रम के प्रभाव"** पर एक अध्ययन किया । अध्ययन के उद्देश्य और निष्कर्ष इस प्रकार थे: अध्ययन के उद्देश्य थे: (1) छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि पर मिड डे मील कार्यक्रम की भूमिका का आकलन करना । (2) उच्च और निम्न आर्थिक स्थिति (यानी एमएपीएल और बीपीएल) से संबंधित छात्रों के बीच मिड डे मील के सापेक्ष प्रभावों की जांच करना । (3) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों पर मिड डे मील के प्रभाव की तुलना करना । अध्ययन की खोजें: यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मिड डे मील कार्यक्रम का कुछ चयनात्मक मामलों में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है (जैसे नामांकन बढ़ाने, उपस्थिति और छात्रों को कम करना और ड्रॉप आउट करना) जो विशेष रूप से छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं । पश्चिम बंगाल राज्य में बर्धमान जिले के उच्च प्राथमिक स्कूलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बीपीएल स्तर के छात्रों से संबंधित हैं । कई प्रतिगमन के परिणामों ने यह संकेत दिया कि छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जो कि कारकों को ध्यान में रखते हुए-नामांकन, उपस्थिति, प्रतिशोध और छात्रों को छोड़ना है ।

2.3.0. **प्रतिबिंब**:

उपरोक्त उद्धृत शोधों से यह कल्पना की जा सकती है कि प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे कि मध्यान भोजन के संबंध में बहुत सारे काम किए गए हैं, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा का अधिकार अधिनियम -2009 लेकिन प्राथमिक विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समितियों द्वारा किए गए कामों से होने वाले बदलाव पर कोई प्रत्यक्ष काम नहीं किया गया है । इसलिए शोधकर्ता ने समस्या पर काम करने का निर्णय लिया है "प्राथमिक विद्यालय चिखली कलाँ पर विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्य प्रणाली की प्रभाव शीलता का अध्ययन ।"